दिनांक–09.10.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पश्चिम चंपारण जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से 09 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2015–16 की 02, 2018–19 की 02, 2019–20 की 01 एवं 2020–21 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी दो दिनो के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, 12वॉ वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 13वॉ वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। DDC द्वारा बताया गया कि प्रतिनिधि भत्ता में 10 करोड़ रूपये की UC एक सप्ताह के भीतर तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

कृ0पृ0उ0

(ख) Post CFMS Period में कुल 353.46 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता, ग्राम कचहरी न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव की नियत फीस एवं एम0एन0वाई0(पेयजल) की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGSA- लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2022–23 तक का कुल 08.93 लाख रूपये की UC लंबित है। निदेश दिया गया कि उक्त के संबंध में UC तैयार विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 6115 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 2957 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 2657 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

V. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1206 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 1168 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 21 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 17 मामलों के विरूद्ध 10 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

VII. CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 07 मामले लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग–इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग–इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः कुल 145, 125 एवं 126 Aspiration के विरूद्ध 85, 125 एवं 125 का निष्पादन किया गया है। जुन, जुलाई एवं अगस्त माह में BPRO द्वारा क्रमशः कुल 03, 09 एवं 09 आवेदनो का Mapping ही नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही निदेश दिया गया कि सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 96 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 89 का हस्तांतरण हो चुका है। बगहा–1, बैरिया, नरकटियागंज एवं सिकटा प्रखंड में 01–01 एवं मझौलिया प्रखंड में 02 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंडो के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 89 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 89 में RTPS केन्द्र, 89 में विद्युत कनेक्शन, 21 में डाकघर, 14 में NOFN एवं 19 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

लगातार.....

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 89 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 76 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 17 PSB के विरूद्ध 16 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 01 पंचायत में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 15 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 12 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से एक का भी निराकरण नहीं हुआ है। 05 पंचायतों में PSB के निर्माण हेतु नयी भूमि प्राप्त हो गयी है। 03 पंचायतों में जमाबंदी रद्दीकरण की प्रक्रिया चल रही है। सिसवा मंगलपुर पंचायत में भूमि अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबंधित BPRO ADM कार्यालय से समन्वय कर जमाबंदी रद्दीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही नयी भूमि प्राप्त पंचायतों में यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 17 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध 15 पंचायतों में भूमि उपलब्ध है, जिसमें से TA द्वारा सभी 15 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। 15 पंचायतो में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 03 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है। जिन पंचायतों में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

X. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 303 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 98 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से 21 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 21 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से एक में भी व्यय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। सभी 21 पंचायतों का प्राक्कलन अबतक LAEO के कार्यपालक अभियंता के पास ही लंबित है। DPRO को निदेश दिया गया कि LAEO के कार्यपालक अभियंता से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 400 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। नरकटियागंज प्रखंड के 27 पंचायतों में 122 शमशान का सर्वेक्षण किया गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से सही प्रतीत नहीं होता है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 24, पंचायत समिति में 131 एवं ग्राम पंचायत में 244 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	21.72%
02	पंचायत समिति	66.67%

लगातार.....

03	ग्राम पंचायत	69.17%

गौनाहा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) यह भी पाया गया है कि पश्चिम चंपारण जिले के लगभग सभी प्रखंडो के पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में Availble Balance के विरूद्ध Balance Liabilities बहुत अधिक है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

(ग) भीटाहा, जोगापट्टी एवं नौतन प्रखंड में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में शून्य राशि का व्यय किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(घ) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1585 के विरूद्ध 100, पंचायत समिति में 2649 के विरूद्ध 172 एवं ग्राम पंचायत में 16177 के विरूद्ध 586 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(ड़) 15 लाख से उपर जिला परिषद में कुल 02 एवं ग्राम पंचायत में 03 Schemes ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. गौनाहा प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. DDC एवं DPRO पश्चिम चंपारण जिले के पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओ की गहन समीक्षा कर एक सप्ताह के भीतर संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं मे राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओ को Abandoned करें।
3. BPRO भीटाहा, जोगापट्टी एवं नौतन पंचायत के पंचायत सचिव कि विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु DPRO को प्रतिवेदित करें।
4. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
5. DDC एवं DPRO जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत में विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. षष्ठ्म राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग

लगातार.....

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
जिला परिषद्	17.18%
पंचायत समिति	40.39%
ग्राम पंचायत	21.59%

मधुबनी, मझौलिया, सिधाव, रामनगर एवं चनपटिया प्रखंडो के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) बगहा प्रखंड में 06, नरकटियागंज प्रखंड में 05, भीटाहा एवं रामनगर प्रखंड में 04–04, सिकटा प्रखंड में 03, चनपटिया, जोगापट्टी, मझौलिया एवं नौतन प्रखंड में 02–02, गौनाहा, लौरिया, मधुबनी, सिधाव एवं ठकराहन प्रखंडो में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

जोगापट्टी एवं चनपटिया प्रखंडो के 09–09 पंचायतो में इस वित्तीय वर्ष व्यय की गयी राशि 15% से भी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 794 के विरूद्ध 200, पंचायत समिति में 988 के विरूद्ध 147 एवं ग्राम पंचायत में 5390 के विरूद्ध मात्र 871 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. मधुबनी, मझौलिया, सिधाव, रामनगर एवं चनपटिया प्रखंडो के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

   DPRO जोगापट्टी एवं चनपटिया प्रखंडो का स्थलीय भ्रमण कर निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर विभाग का प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक पश्चिम चंपारण जिले में 12730 लक्ष्य के विरूद्ध 12530 लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

लगातार.....

साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की संख्या क्रमशः 571 एवं 04 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एजेंसी द्वारा Bill Submit करने के उपरांत भी कुल 03 प्रखंडों में एजेंसी का शून्य राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही मझौलिया, चनपटिया एवं बैरिया प्रखंडो में भुगतान का प्रतिशत काफी कम है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 17 मामलो के विरूद्ध 14 का निष्पादन हो चुका है।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 08.10.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 90% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से बैरिया प्रखंड में ON पाई गई लाइटो का प्रतिशत कम है।

यह भी पाया गया कि कुल 17 प्रखंडो में से 12 प्रखंडो के BPRO के द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनो के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं JICR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा बैरिया प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

भीटाहा, जोगापट्टी, मधुबनी, मैनाटार एवं सिधाव प्रखंडों के BPRO से इस संबंध में विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–03)

XV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

XVI. लंबित न्यायिक वाद :–

पश्चिम चंपारण जिले में 02 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–9)

XVI. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVII. विधान सभा/परिषद–

पश्चिम चंपारण जिले में कुल 16 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

XVIII. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में भी 34 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/5223/पं०रा० पटना, दिनांक 27/10/2026

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पश्चिम चंपारण/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/5223/पं०रा० पटना, दिनांक 27/10/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/5223/पं०रा० पटना, दिनांक 27/10/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी